suffer. The absence of Ambulance Van and X-Ray machine causes a great risk to the lives of the patients. Therefore, I demand that the Ministry of Labour should take immediate steps to upgrade the ESI Hospital of Barbil with all facilities that are badly needed to save the poor workers from untimely death.

(v) Supply of paddy to rice mills in Tamil-Nadu

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : Tamil Nadu is reeling under unprecedented drought and this has been confirmed by our hon. Prime Minister who recently visited some parts of Tamil Nadu and who announced on the spot Rs. 10 crores for drought relief works. The consequence of the failure of two monsoon rains last year has been steep decline in agricultural production. There is acute paddy scarcity throughout Tamil Nadu. There are nearly 10,000 rice mills in the State employing lakhs of workers. They are all facing closure, which would mean throwing out of employment all these workers. The impact of this can be best explained by the fact that about 20,000 workers in 200 Rice Mills in Coimbatore District are on the streets now, since there is no paddy available in Tamil Nadu.

The Godowns of Food Corporation of India are full of paddy. Being the national organisation, the Food Corporation of India should release immediately substantial quantities of paddy for these rice mills. The rice can be taken over by the Food Corporation of India. Through this method only lakhs of workers in these rice mills can be saved from starvation death. It is demanded that the Government of India should come to the rescue of these workers in the rice mills in Tamil Nadu.

(vi) Need for re-classification of different cities of the country.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सन् 1981 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण देश की जनसंख्या 68 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब तक तो वह 70 करोड़ हो चुकी होगी। जनगणना से यह भी स्पष्ट है कि देश के प्रायः सभी छोटे-बड़े नगरों एवं शहरों की आबादी पहले की तुलना में अधिक हो चुकी है।

जनसंख्या में वृद्धि के बाद यह आवश्यक हो गया है कि, सरकार शहरों एवं नगरों के पुनर्वर्गीकरण की घोषणा अविलम्ब कर दे। ऐसी घोषणा तो जनगणना का काम पूरा हो जाने के ठीक बाद ही हो जानी चाहिए थी। ऐसा करने से देश के 36 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हाऊस-रेंट अलाउंस, सिटी कम्पेंसेटरी अलाउंस आदि में वृद्धि का लाभ मिल जाता।

बिहार की राजधानी पटना नगर की जनसंख्या आठ लाख से अधिक हो चुकी है। अभी उसका दर्जा बी-2 का है जिसके अनुसार ही वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उक्त सुविधायें मिल रही हैं। परन्तु, अब वहां जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के बाद निश्चित रूप से पटना नगर का दर्जा बी-1 का हो गया है जिसकी घोषणा होते ही वहां बारह हजार से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कम्पेंसेटरी अलाउंस आदि के नाम पर अधिक राशि मिलना आरंभ हो जाएगा जिससे आज की मंहगाई में उन्हें कुछ राहत मिलने लगेगी।

अतः गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध होगा कि, वह पटना नगर समेत देश के तमाम नगरों के पुनर्वर्गीकरण की घोषणा बिना किसी बिलम्ब के कर दें ताकि सरकारी कर्मचारियों का असंतोष दूर हो सके।